सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-84
23/02/2016

रेल का जिस दिन निजीकरण होगा, देश की एकता पर भयंकर चोट होगी :– मुख्यमंत्री

पटना, 23 फरवरी 2016 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि रेलवे का जिस दिन निजीकरण होगा, देश की एकता पर भयंकर चोट होगी। देश की एकता में रेलवे की बड़ी भूमिका है। आज भी आम आदमी की सवारी रेलवे है। रेलवे का निजीकरण नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि रेलवे का विकास इस प्रकार से होना चाहिये कि उसका लाभ सबों को मिले। देश भर के लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि जो हमारे रिमोट एरिया हैं और रेल सेवा से वंचित हैं, वहॉ रेल पहुॅचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल बजट से मुझे कोई उम्मीद नहीं बची है। हमारे समय के बिहार में इतने रेलवे प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं, उसको पूरा करने के लिये समय सीमा कब की बीत चुकी है, वह पूरा नहीं हुयी है। इसे पूरा करने के लिये धन खर्च करना होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे का विकास केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है। रेलवे उनके नियंत्रण में है। रेलवे को निजीकरण करने की योजना चल रही है। हमारे यहॉ रेलवे के बहुत से प्रोजेक्ट वर्षों से स्वीकृत हैं लेकिन उसे पूरा करने के लिये नाम मात्र के लिये पैसे का आवंटन होता है और काम पूरा नहीं हो पाता है। रेल मंत्री कह रहे हैं कि रेल के प्रोजेक्ट में राज्य सरकार भी पैसा लगाये। केन्द्र प्रायोजित किस–किस योजना में राज्य सरकार पैसे लगायेगी। जिसकी जो जिम्मेवारी है, पूरा करना चाहिये। देश के प्रगति की जवाबदेही केन्द्र और राज्य दोनों की है। हमलोगों के जिम्मे जो काम है, हमलोग करते हैं। केन्द्र के जिम्मे जो काम है, केन्द्र सरकार करे। उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि रेलवे को जितना धन चाहिये, केन्द्र सरकार देने की स्थिति में नहीं हैं इसलिये वे हर जगह प्राइवेट इनवेस्टमेंट की बात करते हैं। जितना रेलवे को केन्द्र सरकार से सहायता मिलना चाहिये, वह सहायता भी नहीं मिल पा रही है। रेलवे का भी खस्ताहाल है। उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामना पुराने मित्र रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी के साथ है।

पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आर0एस0एस0 प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण के ऊपर अपनी टिप्पणी दी थी और ये सारी बातें आर0एस0एस0 के लोकपत्र पांचजन्य में छपी थी। उन्होंने उस समय भी यही बात कही थी कि राजनीतिक समिति बननी चाहिये। यह तो संवैधानिक व्यवस्था है। सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों को चिह्नित किया गया है, उससे अलग हटकर संवैधानिक व्यवस्था से अलग वे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान के इतर एक संस्था यानी एक्स्ट्रा कन्सच्यूशनल ऑथोरिटी की तरह वह काम करे। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये लोग अंबेडकर साहब के चित्र पर माल्यार्पण करते हैं और दूसरी तरफ भारत के संविधान को जड़ मूल से समाप्त करने पर तुले हुये हैं। आरक्षण के बारे में उन्होंने जो कहा है, उनके विचार हैं और अंततोगत्वा जो आर0एस0एस0 का विचार है, वही भाजपा का भी विचार है। सार्वजनिक रूप से मौके–बेमौके वे अपनी दूरी बनाकर रखना चाहते हैं लेकिन यह दूरी दिखावटी है। केन्द्र सरकार में आज जो लोग हैं, उनकी विचारधारा वही है जो आर0एस0एस0 की है। उनका मत साफ है कि इस देश में दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों को आरक्षण मिला है,

उस आरक्षण से वे नाखुश हैं। आरक्षण उनके हितों के खिलाफ है, फिर उन्होंने इस बात को दुहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज संविधान की व्यवस्था का मजाक उड़ रहा है। जे0एन0यू0 प्रकरण में आज जो विडियो सामने आया है, उसके हिसाब से वकील साफ गाली देते हुये बोल रहे हैं कि हमने उसको पीटा और पुलिस वहीं खड़ी थी और ये सारी बातें विडियो में कही गयी है। इसके बाद भी कह रहे हैं कि हम अंदर जाकर सेल में पिटाई करेंगे। इस बात से साफ है कि केन्द्र सरकार की तरफ से कानून का राज नहीं है। दिल्ली पुलिस तो केन्द्र सरकार के अधीन है। गृह मंत्रालय के अधीन है और दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। जिस तरह से ये सारी चीजें आ रही है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली में जंगलराज है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो जायेगा, जिसकी पेशी हो रही है और उस पर हमला हो तो फिर क्या बचता है। यहॉ के कुछ वारदातों पर ये लोग रोज बोलते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इनका इरादा देश में फासिज्म लाना है। इनके विचारधारा से जो असहमत हैं, सबको देशद्रोही घोषित करना। चूँकि आर्थिक मोर्चे पर पूरे तौर पर ये विफल हो चुके हैं। अपने वायदों को निभाने में नाकामयाब रहे हैं। न काला धन आया, न युवाओं को रोजगार मिला, न देश का विकास दर बढ़ा, न देश में कोई इनवेस्टमेंट आ रहा है। ये चाहे कितना भी नारा दे दें, जो पैमाना है इसको बदलकर ये दिखाना चाहते हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ा है। बैंकों की हालत खस्ता है, इनका पैसा डूब चुका है। ऐसी परिस्थिति में आर्थिक मोर्चे पर विफलता को छिपाने के लिये और मूल मुद्दे से देश को किनारा करने के लिये भावनात्मक मुद्दे लाकर देश को बॉटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अंततोगत्वा सता के बल पर अपने विचारधारा को थोपना चाहते हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह के विचारधारा से तमाम वे लोग जो असहमत हैं, जितने लोकतांत्रिक, समाजवादी एवं साम्यवादी शक्तियॉ हैं, सबको एकजुट होना होगा और इसके फासीवाद का मुकाबला करना होगा। इसके लिये जो भी कुर्बानी देना पड़े, तैयार रहना चाहिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने विचारधारा को थोपेंगे, जो इनके विचारधारा से असहमत होंगे, उन्हें देशद्रोही करार दिया जायेगा। आज की तारीख में ये बता नहीं पाये कि जे0एन0यू0 छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कौन देशद्रोह की बात की। उन्होंने कहा कि हमलोग कभी भी कोई भारत के खिलाफ बोलेगा या भारत के खिलाफ नारा लगायेगा, उसका समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को बंद किया गया, उसके विडियो से छेड़छाड़ करके उसको फॅसाने की कोशिश हो रही है, ये बातें जगजाहिर हो गयी है। उन्होंने कहा कि भूखमरी, पूँजीवाद एवं सामंतवाद के खिलाफ नारा लगाना अगर देशद्रोह है तो इसके बारे में लोगों को साफ समझ लेना चाहिये। ये अपना विचार लोगों पर थोपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे गलतफहमी के शिकार हैं कि वे अपने अफवाह फैलाने की शक्ति और प्रचार की शक्ति के बदौलत देश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, यह उनका भ्रम है। उन्होंने कहा कि जब –जब देश के लोगों पर इस प्रकार के आक्रमण करने की कोशिश की गयी, पूरा देश एकजुट हुआ है और इसका करारा जवाब मिला है।

पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जाट आरक्षण की बात है, इसमें ये बात साफ है कि इनके पार्टी के लोगों ने जाट के खिलाफ वक्तव्य दिया। चुनाव के दौरान कहा था कि जाटों को आरक्षण देंगे और उससे मुकर गये। इस प्रकार की परिस्थिति की पूरी जिम्मेवारी इनकी है और इनके नेताओं की है। अगर ये आरक्षण नहीं दे सकते थे तो चुनाव में क्यों कहा। इस मुद्दे को वे टालते जा रहे थे। कुछ नेता जाट समाज के खिलाफ बोलने लगे तो जाटों के मन में भावना भड़क गयी। यह आन्दोलन तो था नहीं, ऐसा लगा कि स्वतः स्फूर्त

है। उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों से कहूँगा कि शांति बनाये रखें। उन्होंने कहा कि अहिंसा के रास्ते अपनी बातें रखनी चाहिये। हिंसा के सहारे इस देश में कोई बात नहीं हो सकती है। हिंसा को न तो कोई तरजीह देगा और न कोई समर्थन करेगा। ये जो पूरी परिस्थिति पैदा हुयी है, इसके लिये केन्द्र सरकार जिम्मेवार है। एक तरफ तो इन्होंने गोली चलवाये और जो मर गये, उनकी मुआवजा का भी एलान कर रहे हैं। जो मर गये, उनकी जान तो वापस नहीं आयेगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह ये पिट चुके हैं और इसलिये इस देश को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर सता में बने रहना चाहते हैं। अपना विचार लोगों पर थोपना चाहते हैं, इसमें वे कामयाब नहीं होंगे।

******